

महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह

बनाम

बिहार राज्य

(एस. आर. दास, सी.जे., एन. एच. भगवती और एम. हिदायतुल्ला, जे.जे.)

कृषि आयकर- कृषि आयकर अधिकारी की शक्ति- यदि वह छूट के अपने आदेश को संशोधित कर सकता है- बिहार कृषि आयकर अधिनियम, 1938 (1938 का बिहार VII) धारा. 26.

निर्धारण वर्ष 1944-45 के लिए कृषि आय के अपने रिटर्न में अपीलकर्ता ने पूंजीगत रसीद के रूप में उनके द्वारा दावा की गई कटौती की कुल राशि में से एक के रूप में 2,82,192 रुपये की राशि दिखाई, जो उन्होंने ज़ारपेशगी पट्टे पर ली गई दो लीज- होल्ड संपत्तियों के लिए टेकरी राज को भुगतान किया था, कृषि आयकर अधिकारी ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया और राशि को कृषि आयकर के भुगतान से छूट दे दी। कृषि आयकर के सहायक निगमायुक्त ने निर्णय की पुष्टि की। एक डिमांड नोटिस जारी किया गया और निर्धारिती ने दो किस्तों का भुगतान किया। इसके बाद, कृषि आयकर अधिकारी ने निर्धारिती को धारा 26 बिहार कृषि आयकर अधिनियम, 1938 के तहत एक नोटिस इस आशय का दिया कि उक्त ज़रपेशगी पट्टे से आय मूल्यांकन से बच गई थी और उसके उपस्थित होने के बाद, एक अनुपूरक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया

और 39,512-6-0 रुपये. कर के रूप में मूल्यांकन किए गए। निर्धारिती ने अपील की। कृषि आयकर आयुक्त ने उक्त निर्णय को उलट दिया। बिहार माक प्रांत ने राजस्व बोर्ड को स्थानांतरित किया और अधिनियम के 25(1) के तहत दोप्रश्न सर हाई कोर्ट को भेजे, (1) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कृषि आयकर अधिकारी के पास धारा 26 अधिनियम के तहत अपने आदेश को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र था और (2) यदि हां, तो क्या ज़ारपेशगी पट्टे से होने वाली आय अधिनियम के तहत कर योग्य थी। हाई कोर्ट ने दोनों सवालों का जवाब बिहार राज्य के पक्ष में दिया. इसलिए निर्धारिती द्वारा विशेष अनुमति द्वारा यह अपील की गई है। माना, कि धारा 26 बिहार कृषि आयकर अधिनियम, 1938 के तहत, कृषि आयकर अधिकारी को अपने स्वयं के आदेश को संशोधित करने और आय की एक वस्तु का आकलन करने की शक्ति थी, जिसे रिटर्न में दिखाए जाने के बावजूद, उसने पहले एक गलतफहमी के तहत कि यह कर योग्य नहीं था, कर लगाना छोड़ दिया था।

अधिनियम की धारा 26 में "किसी भी कारण" शब्दों के प्रयोग ने धारा को धारा 34 भारतीय आयकर अधिनियम से अधिक व्यापक बना दिया, उन शर्तों को समाप्त कर जो बाद वाले खंड को सीमित करती हैं।

कमल सिंह बनाम आयकर आयुक्त, बीकर और उड़ीसा, ए.एल.आर. 1959 एस.सी. 257,लागू।

मेर्स. चट्टूराम होरिलराम एल. बनाम आयकर आयुक्त, बिहार और

उड़ीसा,(1955) एक एस.सी.आर. पहले, प्रतिष्ठित.

केस- कानून पर चर्चा हुई.

चूंकि अपीलकर्ता अपने मामले को साबित करने में विफल रहा था कि विचाराधीन आय उसके धन- उधार व्यवसाय से आय थी या पट्टेदार को किया गया भुगतान प्रीमियम के माध्यम से नहीं बल्कि ऋण के रूप में था, जो कि लीज- बोर्ड संपत्ति से आय, जो कि स्वीकृत रूप से कृषि चरित्र का था, उसे अधिनियम के तहत प्राप्तकर्ता के चरित्र की परवाह किए बिना कर के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए।

सिविल अपीलक्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 254/1954

विविध मामलों में पटना उच्च न्यायालय के 19 फरवरी, 1952 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील। जुडल केस नंबर 244/1949

बी. सेन, 8. के. मजूमदार और आई. एन. श्रॉफ, के लिए अपीलकर्ता
एम.ओ. सीतलवाड,

भारत के अटॉर्नी- जनरल, बी.के. सूरन और आर.सी. प्रसाद, प्रतिवादी
की ओर से।

15 मई 1959. कोर्ट का फैसला था।

हिदायतुल्ला जे. द्वारा दिया गया - यह अपील, इस न्यायालय की

विशेष अनुमति के साथ, महाराजाधिराज दरभंगा के सर कामेश्वर सिंह (बाद में निर्धारिती के रूप में संदर्भित) ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 19 फरवरी, 1952 के खिलाफ दायर की, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 25(1) बिहार कृषि आयकर अधिनियम, 1938 के तहत संदर्भित निम्नलिखित दो प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया।

(1) "क्या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से जिस तरीके से, उचित विचार के बाद, विद्वान कृषि आयकर अधिकारी ने 5 जनवरी, 1946 को अपने पहले फैसले में यह माना था कि निर्धारिती कार्पेशगी पट्टे के कारण प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था, विद्वान कृषि आयकर अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 26 के तहत अपने स्वयं के आदेश को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है; तथा

(2) यदि उसके पास अधिनियम की धारा 26 के तहत अपने स्वयं के आदेश को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र था, तो निर्धारिती के जरपेशगी पट्टे से आय अधिनियम के तहत कर योग्य थी।

मामले के तथ्य बहुत ही संकीर्ण दायरे में हैं। निर्धारण वर्ष 1944-45 के लिए, जो खाता 1351 फसली के वर्ष के अनुरूप था, निर्धारिती ने उनकी कृषि आय 37,43,520 रुपये लौटा दिए हैं। उन्होंने 9,42,137-3-101 रुपये की कटौती का दावा किया, भू- राजस्व, किराया आदि के कारण, 2,82,192 रुपये सहित जो कि भुगतान टेकारी राज को किया गया दिखाया

गया है, जहां से दो लीजहोल्ड संपत्तियां क्रमशः 15 अगस्त 1931 और 31 जनवरी 1936 के अनुबंधों द्वारा सर्पेशगी लीज पर ली गई थीं। राशि को पूंजीगत रसीद के रूप में काटे जाने की मांग की गई थी।

दरभंगा के कृषि आयकर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28 दिसंबर, 1945 द्वारा इस तर्क को स्वीकार कर लिया, और राशि को कृषि आयकर के भुगतान से छूट दे दी। उन्होंने देखा:

"भूमि राजस्व और किराए के कारण दावा किए गए 9,42,137-3-10 रुपये में से, 2,82,192 रुपये को टेकारी राज को भुगतान के रूप में दिखाया गया है और फिर स्वयं के लिए जरपेशगी ऋण की प्राप्ति के लिए लिया गया है। मैंने गया जरपेशगी लीज का बांड की जांच कर ली है। यह भुगतान निर्धारिती को दिया जाता है, क्योंकि बांड की शर्तों के अनुसार यह एक पूंजीगत आय है। उसी समय, मुझे लगता है, यह राशि रु. 2,82,192 को टेकारी राज की आय के रूप में माना जाना चाहिए और टेकारी राज की अन्य आय के साथ गया सर्कल में मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि इसे निर्धारिती द्वारा उस राज में जमा किया जाता है और फिर टेकारी राज को दिए गए जरपेशगी ऋण के खिलाफ सेटकिया जाता है।"

मूल्यांकन को 4 जनवरी, 1946 को कृषि आयकर के सहायक

आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था, और अगले दिन, आयकर अधिकारी ने अपना औपचारिक आदेश पारित किया और एक मांग नोटिस जारी किया।

निर्धारिती ने तीन में से दो किशतों का भुगतान किया जब दिनांक 22 मार्च, 1946 को कृषि आयकर अधिकारी ने निम्नलिखित आदेश दर्ज किया:-

"ऐसा प्रतीत होता है कि गया जरपेशगी लीज से प्राप्त अब कुछ कृषि आय जिस पर टैक्स लगाना चाहिए था वर्ष 1944-45 (1351 फसली) के लिए मूल्यांकन से बच गया है- 20 मई 1947 तारीख तय करते हुए धारा 26 के तहत नोटिस जारी करें"

निर्धारिती के उपस्थित होने के बाद, एक पूरक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया और 39,512-6-0 रुपये को 2,52,879 रुपये पर कर के तौर पर एसेसमेंट किया गया।

मामले को तय करने में, कृषि आयकर अधिकारी ने निम्नलिखित कारण बताये:

"पट्टे की शर्तों के अनुसार निर्धारिती को पट्टे में दी गई भूमि पर कब्जा बनाए रखना है और पट्टादाता को 1,000 रुपये का वार्षिक किराया भुगतान करके निश्चित वर्षों के लिए पट्टे में दी गई भूमि का उपभोग करना है और इस

प्रकार खुद को संतुष्ट करना है। वास्तव में, इस जरपेशगी पट्टे द्वारा निर्धारिती को एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित किराए पर भूमि का अनुदान दिया गया है। इस कार्यकाल के दौरान इन जमीनों से जो भी आय प्राप्त होती है पट्टा, निर्धारिती की आय है और इस प्रकार इस पर कर निर्धारिती के हाथों में लगाया जाना चाहिए, न कि पट्टादाता के हाथों में"

कृषि आयकर अधिकारी के द्वारा बिहार कृषि आयकर अधिनियम, 1938 का 26 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत कार्य करने का इरादा किया गया है।

निर्धारिती ने अपील की। कृषि- सांस्कृतिक आयकर आयुक्त ने निर्णय पलट दिया। उसने संकेत किया कि टेकारी राज संपत्ति से कृषि आय निर्धारिती द्वारा वापस कर दी गई थी, लेकिन उसे छूट दी गई थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता था कि वह मूल्यांकन से बच गई है ताकि मामले को अधिनियम की धारा 26 के भीतर लाया जा सके। बिहार प्रांत (जैसा कि तब इसे कहा जाता था) राजस्व बोर्ड, बिहार के समक्ष व, जिसने 7 फरवरी, 1948 के एक प्रस्ताव द्वारा दोनों प्रश्नों को पटना उच्च न्यायालय को भेज दिया। दोनों सवालों पर बोर्ड ने कोई राय व्यक्त नहीं की। हाई कोर्ट में दोनों सवालों का जवाब बिहार राज्य के पक्ष में दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा छुट्टी अस्वीकार कर दिए जाने पर, निर्धारिती

ने इसके लिए आवेदन किया और इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की।

अधिनियम की धारा 26, जिसके तहत कृषि आयकर अधिकारी को कार्य करने के लिए कहा जाता है, काफी हद तक भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34, इसके संशोधन से पहले, के समान है। इसलिए, आवश्यक रूप से, बाद वाले खंड की व्याख्या पर निर्णयों को प्रतिस्पर्धी दलों द्वारा स्वतंत्र रूप से उद्धृत किया गया था। अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार है:

"यदि किसी भी कारण से कृषि आयकर के दायरे में आने वाली कोई भी कृषि आय किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है, या बहुत कम दर पर एकत्र की गई है, तो कृषि आयकर अधिकारी एक वर्ष के भीतर किसी भी समय उस वित्तीय वर्ष के अंत में, ऐसी कृषि आय पर कृषि आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को या, किसी कंपनी के मामले में, उसके प्रमुख अधिकारी को, "एक नोटिस जिसमें उन सभी या कुछ आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है" जो कि धारा 17 की उप- धारा (2) के तहत एक नोटिस में शामिल की जा सकती है, भेज सकता है और ऐसी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि नोटिस जारी किया गया नोटिस था उस उपधारा के अंतर्गत: बशर्ते कि कर उस दर पर वसूला जाएगा जिस दर पर

यह वसूला जाता यदि ऐसी आय, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन या पूर्ण मूल्यांकन से बच नहीं पाई थी।"संदर्भ की सुविधा के लिए, भारतीय आयकर अधिनियम के 1948 में संशोधन से पहले की धारा 34 को भी यहां उद्धृत किया जा सकता है। "यदि निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप जो उसके पास आई है, आयकर अधिकारी को पता चलता है कि आयकर के लिए प्रभार्य आय, लाभ या लाभ किसी भी वर्ष मूल्यांकन से बच गए हैं, या उनका कम मूल्यांकन किया गया है, या उनका बेहद कम दर पर मूल्यांकन किया गया है, या इस अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय रहा है, आयकर अधिकारी किसी भी मामले में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती ने अपनी आय का विवरण छुपाया है या जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद, आठ साल के भीतर किसी भी समय, और किसी भी अन्य मामले में उस वर्ष के अंत के चार साल के भीतर किसी भी समय, ऐसी आय, लाभ या लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सेवा प्रदान करें, या किसी कंपनी के मामले में, उसके प्रधान अधिकारी पर, एक नोटिस जिसमें सभी या किसी भी आवश्यकताएं शामिल हैं जो धारा 22 की उप- धारा (2) के तहत एक नोटिस में शामिल की जा सकती हैं, और ऐसी आय, लाभ या का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। लाभ, और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि नोटिस उस उप- धारा के तहत जारी किया गया नोटिस था

बशर्ते कि कर उसी दर पर वसूला जाएगा जिस दर पर यह लगाया जाएगा यदि आय, लाभ या लाभ मूल्यांकन या पूर्ण मूल्यांकन से बच नहीं गए हों, जैसा भी मामला हो"

संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या वह आय जो लौटा दी गई थी लेकिन कर से मुक्त रखी गई थी, उसे "आकलन से बच गई" कहा जा सकता है ताकि कृषि आयकर अधिकारी अधिनियम की धारा 26 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग इस पर कर लगाने के लिए कर सके। यह सवाल जो कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 के तहत उठ रहा है पर कई अवसरों पर उच्च न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि राय की प्रबलता यह मानने के पक्ष में है कि ऐसी आय को मूल्यांकन से बेचने के लिए कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेते हुए कि कृषि आयकर अधिकारी के पास अपने पहले के मूल्यांकन को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र था, धारा 26 के शुरुआती शब्दों का उल्लेख किया। अर्थात्, "किसी भी कारण से" और देखा कि यह था "पलायन" शब्द को एक प्रतिबंधित अर्थ देना आवश्यक नहीं है, और यदि कर लगाने वाले अधिकारियों की ओर से किसी गलती या चूक के कारण आय की किसी वस्तु पर कर नहीं लगाया गया था, तो वह वस्तु "पलायन" शब्द के अंतर्गत आ सकती है। ". उच्च न्यायालय के अनुसार, वाक्यांश "मूल्यांकन से बच गया" उन मामलों तक

ही सीमित नहीं था जहां कोई अनजाने में चूक हुई थी, बल्कि अनुभाग के बाद के भाग को ध्यान में रखते हुए "जहां आय... का मूल्यांकन बहुत कम दर पर किया गया है", एक ऐसा मामला शामिल है जहां जानबूझकर कार्रवाई की गई थी।

निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि "किसी भी कारण" शब्दों की व्यापकता का "बच गए मूल्यांकन" शब्दों के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि "मूल्यांकन" शब्द कर आय के अंतिम निर्धारण को नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। जिसके द्वारा परिणाम पर पहुंचा जाता है, और चूंकि आय वास्तव में वापस कर दी गई थी और छूट दी गई थी, इसलिए "बच गए मूल्यांकन" का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि यह आय के प्रसंस्करण से गुज़रा था। उनका यह भी तर्क है कि अनुभाग का बाद वाला भाग जो बहुत कम दर पर मूल्यांकन से संबंधित है, को यह निर्णय लेने में सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है कि कब आय को मूल्यांकन से बचा हुआ कहा जा सकता है। उनका कहना है कि यह धारा उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां आय वापस कर दी जाती है लेकिन कर के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है और निम्नलिखित मामलों पर भरोसा किया जाता है; महाराजा बिक्रम किशोर बनाम असम प्रांत (), आयकर आयुक्त बनाम डे ब्रदर्स (), मदन मोहन लाल बनाम आयकर आयुक्त () (प्रति दलीप सिंह, जे.) और चिमनराम मोल (सोना और चांदी)), बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बॉम्बे ("

(कानिया,

जे. के अनुसार, जैसा कि तब था)।

विद्वान अटॉर्नी- जनरल ने न्यायालय का ध्यान अन्य मामलों की ओर आकर्षित किया जिसमें यह विचार लिया गया है कि भले ही आय वापस कर दी जाए और जानबूझकर कर नहीं लगाया जाए, धारा के लागू होने के लिए आवश्यक शर्त पूरी हो जाती है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित मामलों का हवाला दिया: एंग्लो- फारसी ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1), पी. सी. मुलिक और डी. सी. आइच, इन री ("), द

आयकर आयुक्त बनाम पार्लोकिमेडी के राजा (1) चिमनराम मोती लाल (सोना और चांदी), बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बॉम्बे (") और मदन मोहन लाल बनाम आयकर आयुक्त ("). विद्वान अटॉर्नी- जनरल ने भी कमल सिंह बनाम कॉमिस में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। इनकम- टार, बिहार और उड़ीसा का तीसरा भाग ("), जहां गजेंद्रगडकर, जे. ने सभी प्राधिकारियों की समीक्षा के बाद माना कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 ऐसे मामले पर लागू होती है जहां एक आय का हिस्सा वापस कर दिया गया था, लेकिन जानबूझकर और विचार करने के बाद, कर के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया था। निर्धारिती के विद्वान वकील का तर्क है कि उस मामले में बिंदु खुला छोड़ दिया गया था, और मेसर्स चट्टराम होरिलराम लिमिटेड बनाम आय-कर

आयुक्त, बिहार और उड़ीसा(") को इसके विपरीत माना गया है।

उच्च न्यायालयों के अन्य प्राधिकारियों का उल्लेख करने से पहले यह देखना उचित होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के दो मामले सही हैं या नहीं, और यदि हां, तो उनमें से कौन से हैं। कमल सिंह के मामले में (), मुद्दा निम्नलिखित परिस्थितियों में उठा। उस मामले में अपीलकर्ता के पिता का वर्ष 1945-46 के लिए आयकर निर्धारण किया गया था। आयकर के लिए निर्धारित कुल आय रु. 1,00,000 जिसमें रुपये की राशि शामिल थी। संग्रहण शुल्क की कटौती के बाद बकाया किराए पर ब्याज के कारण उन्हें 93,604 रुपये प्राप्त हुए। आयकर अधिकारी के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि कामाक्ष्य नारायण सिंह बनाम आयकर आयुक्त () में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, यह ब्याज कृषि आय होने के कारण आयकर के लिए मूल्यांकन योग्य नहीं है। आयकर अधिकारी ने इस तर्क को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रिवी काउंसिल के समक्ष एक अपील लंबित थी। अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि आयकर अधिकारी उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है, और उन्होंने आदेश को रद्द कर दिया और आयकर अधिकारी को नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इसके बाद आयकर अधिकारी ने राशि काट ली और केवल शेष आय (कुछ मामूली समायोजन के बाद) को कर के दायरे में लाया गया। उनका आदेश 20 अगस्त 1946 को पारित हुआ। वर्ष 1948 में प्रिवी

काउंसिल ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। जज. प्रिवी काउंसिल का विवरण आयकर आयुक्त बनाम कामाक्ष्य नारायण सिंह () में बताया गया है। इसके बाद आयकर अधिकारी ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 के तहत एक नोटिस जारी किया और पक्ष की सुनवाई के बाद कुल राशि 93,604 रु. का मूल्यांकन किया।

विविध प्रक्रिया के बाद, जिसका विवरण देना आवश्यक नहीं है, मामला इस न्यायालय में पहुंचा, और जो प्रश्न उसके समक्ष था वह था "क्या मामले की परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 34 के तहत बकाया किराया पर ब्याज का मूल्यांकन आदेश दिया जाना कानूनी है।"

दो प्रश्न शामिल थे. पहला यह था कि क्या "सूचना" शब्द इतना व्यापक था कि इसमें कानून की स्थिति के बारे में या कानून के किसी मुद्दे पर निर्णय के बारे में ज्ञान शामिल हो सके। इस बात से हमें इस मामले में कोई सरोकार नहीं है. दूसरा, जब यह कहा जा सकता था कि आय मूल्यांकन से बच गई है। तर्कों में "मूल्यांकन" शब्द पर जोर दिया गया था, और यह तर्क दिया गया था कि यह न केवल मूल्यांकन के आदेश को दर्शाता है, बल्कि इसमें "कर लगाने के उद्देश्य से और कराधान की प्रक्रिया के दौरान उठाए गए सभी कदम" शामिल हैं। यह भी तर्क दिया गया कि "पलायन" का मतलब है कि आय अवलोकन, खोज आदि से बच गई होगी, या दूसरे शब्दों में, आयकर अधिकारी के नोटिस से बच गई होगी। हालाँकि, गजेंद्रगडकर, जे. ने इस वाक्यांश को इतने संकीर्ण अर्थ तक सीमित नहीं रखा। उसने देखा;

"यहां तक कि अगर निर्धारिती ने अपनी आय का रिटर्न जमा कर दिया है, तो भी ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पूरी आय का मूल्यांकन नहीं किया गया है और आय का ऐसा हिस्सा जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है उसे मूल्यांकन से बचा हुआ माना जा सकता है। वर्तमान में मामले में, निर्धारिती द्वारा अपनी कृषि भूमि से प्राप्त किराए को आयकर अधिकारी के ध्यान में लाया गया; इस सवाल पर कि क्या उक्त राशि का कानून में मूल्यांकन किया जा सकता है, पर विचार किया गया और अंततः यह माना गया कि प्रासंगिक निर्णय -पटना उच्च न्यायालय का आदेश जो कि विभाग पर बाध्यकारी था, ने निर्धारिती के दावे को उचित ठहराया कि उक्त आय कर के निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती की आय के एक हिस्से का मूल्यांकन नहीं किया गया था और इस अर्थ में, यह स्पष्ट रूप से मूल्यांकन से बच गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि, क्योंकि मामले पर विचार किया गया था और पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाध्यकारी अधिकार के आलोक में गुण- दोष के आधार पर निर्णय लिया गया था, कोई भी आय मूल्यांकन से नहीं बची है, जब उक्त पटना उच्च न्यायालय के फैसले को प्रिवी काउंसिल ने बाद में पलट दिया गया हो? हमें यह मानने

का कोई औचित्य नहीं दिखता कि मूल्यांकन से बचने वाली आय के मामले हमेशा ऐसे मामले होने चाहिए जहां आय का मूल्यांकन असावधानी या चूक के कारण या इस तथ्य के कारण नहीं किया गया है कि कोई रिटर्न जमा नहीं किया गया है। हमारी राय में, ऐसे मामले में भी जहां रिटर्न जमा कर दिया गया है, यदि आयकर अधिकारी गलती से मूल्यांकन योग्य आय के एक हिस्से पर कर लगाने में विफल रहता है, तो यह एक ऐसा मामला है जहां आय का उक्त हिस्सा मूल्यांकन से बच गया है। अपीलकर्ता ने धारा 34(1) (बी) में 'पलायन' शब्द के अर्थ पर एक बहुत ही संकीर्ण और कृत्रिम सीमा लगाने का प्रयास किया। इसलिए सफल नहीं हो सकता।"

निर्धारिती उस मामले को इस आधार पर अलग करना चाहता है कि इस न्यायालय ने विशेष परिस्थितियों में कानून बनाया था जहां कानून की एक नई व्याख्या दी गई थी, और यह आयकर अधिकारी द्वारा अपना मन बदलने का मामला नहीं था। उनका तर्क है कि कम से कम कुछ जानकारी आयकर अधिकारी के पास आई थी, जिस पर उनकी आगामी कार्रवाई टिकी हो सकती थी। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गजेंद्रगडकर, जे. ने स्पष्ट रूप से प्रश्न को खुला छोड़ दिया था, जहां कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आयकर अधिकारी ने किसी बाहरी स्रोत से किसी भी जानकारी के बिना

अपना मन बदल दिया। इस संबंध में निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है:

"ऐसा प्रतीत होता है कि, धारा 34 के प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को समझने में, उच्च न्यायालयों को यह निर्णय लेने का अवसर मिला है कि क्या आयकर अधिकारी द्वारा धारा 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इस आधार पर कि वह सोचता है मूल्यांकन का क्रम बनाने में उनका मूल निर्णय किसी बाहरी स्रोत से किसी ताजा जानकारी के बिना गलत है या क्या आयकर अधिकारी का उत्तराधिकारी धारा 34 इस आधार पर कि उनके पूर्ववर्तियों द्वारा पारित मूल्यांकन का आदेश गलत था, कार्यवाही कर सकता है और इस बिंदु पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। प्रतिवादी के लिए श्री राजगोपाल शास्त्री ने सुझाव दिया कि 1948 में संशोधित धारा 34 के प्रावधानों के तहत, आयकर अधिकारी के लिए उक्त धारा के तहत कार्य करना खुला होगा, भले ही उसने किसी बाहरी स्रोत से किसी भी जानकारी के बिना अपना मन बदल लिया हो और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि, किसी विशेष मामले में, उसने गलती से एक निर्धारिती की आय को मूल्यांकन से बचने की अनुमति दे दी गई। हम वर्तमान अपील में इस बिंदु पर

कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।"

हम तुरंत कह सकते हैं कि अधिनियम की धारा 26 के शब्दों में कुछ नई जानकारी रखना या प्राप्त करना शामिल नहीं है। धारा कहती है:

"यदि किसी भी कारण से कोई कृषि आय हो कृषि आयकर के दायरे से बाहर हो गया है किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यांकन.....कृषि- सांस्कृतिक आयकर अधिकारी.....आगे बढ़ सकते हैं आकलनकरें.....ऐसी आय....."

"किसी भी कारण" शब्दों का उपयोग, जो व्यापक आयात के हैं, उन शर्तों से छूट देते हैं जिनके द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 परिचालित होती है। जिस बिंदु को इस प्रकार गजेंद्रगडकर, जे. द्वारा छोड़ दिया गया था, वह उस अधिनियम के संदर्भ में उत्पन्न नहीं हो सकता है जिस पर हम काम कर रहे हैं।

इस स्पष्ट राय को देखते हुए, हमारे लिए इस न्यायालय के निर्णय से पहले के मामलों पर दोबारा विचार करना शायद ही आवश्यक है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को गजेंद्रगडकर, जे. के फैसले में माना जाता है। अधिकांश मामलों को महाराजा बिक्रम किशोर बनाम असम प्रांत में

हैरिस, सी.जे., और मुखर्जी, जे. (जैसा कि वह तब था) के फैसले में भी माना जाता है। ()। उन सभी मामलों में जहां विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था, राजेंद्र नाथ मुखर्जी बनाम आयकर आयुक्त (विशेष रूप से एक मार्ग जिसमें यह देखा गया था) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया गया था

"तथ्य यह है कि धारा 34 में उस आय की वापसी के लिए नोटिस देने की आवश्यकता है जो मूल्यांकन से बच गई थी, यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि जो आय पहले ही मूल्यांकन के लिए विधिवत वापस कर दी गई है, उसे वैधानिक अर्थ के भीतर 'मूल्यांकन से बच' नहीं कहा जा सकता है।

"मामले के तथ्य बिल्कुल अलग थे. आय वापस कर दी गई थी, और धारा 34 के तहत नोटिस मिलने पर अभी तक संसाधित नहीं किया गया था। मामले की कुंजी रैंकिन, सी.जे. माननीय की टिप्पणियों के अनुमोदन से सुसज्जित है: लच्छीराम बसंतलाल () कि: "यदि निर्धारिती की आय के मूल्यांकन के लिए उस समय कार्यवाही लंबित है, जो अभी तक उसके अंतिम मूल्यांकन में समाप्त नहीं हुई है, तो आय मूल्यांकन से बच नहीं गई है।

"उन माननीय का मानना था कि अभिव्यक्ति "मूल्यांकन से बच गया है"

को "मूल्यांकन नहीं किया गया है" के समकक्ष के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से "मूल्यांकन शब्द का अर्थ बहुत संकीर्ण हो जाता है और बच गए शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है ।" कि वे टिप्पणियाँ उन माननीय के समक्ष आए उन तथ्यों से संबंधित थी निम्नलिखित से स्पष्ट है गद्यांश

" यह कहने के लिए कि बर्न एंड कंपनी की आय, जिसे जनवरी, 1928 में मूल्यांकन के लिए वापस कर दिया गया था और जिसे सही ढंग से लौटाया गया माना गया था, हालांकि इसे मार्टिन एंड कंपनी के मूल्यांकन में गलती से शामिल किया गया था, 1927-28 में मूल्यांकन से 'बच' गई है उन माननीय को एक अस्वीकार्य पाठन लगता है...उन माननीय को अपील के निपटान के लिए यह पर्याप्त लगता है, क्योंकि वे ऐसा करते हैं कि बर्न एंड कंपनी की आय, धारा 34 के अर्थ के भीतर वर्ष 1927-28 में 'मूल्यांकन से बच' नहीं पाई। "यह मूल्यांकन कार्यवाही की लंबितता के संदर्भ में की गई टिप्पणियां थीं और मामले को निम्नलिखित द्वारा किसी भी संदेह से निर्णायक रूप से साफ़ कर दिया गया है। "ऐसा हो सकता है कि यदि धारा 22 के तहत कर वर्ष के भीतर रिटर्न के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो धारा 34 बताती है कि चूक को दूर करना क्राउन के पास एकमात्र साधन उपलब्ध है, लेकिन यह एक अलग मामला है।

"हमारी राय में, निर्धारिती द्वारा भरोसा किए गए मामलों में त्रुटि

उपरोक्त मामले में डाइटा का उपयोग करने में उत्पन्न होती है, जिस संदर्भ में वे बनाए गए थे और उन्हें तथ्यों पर लागू करना, जहां वे नहीं कर सकते। गजेंद्रगडकर, जे. के फैसले ने मामले को, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, सम्मानपूर्वक, बहुत पर्याप्त रूप से निपटाया है और हम उसी आधार को फिर से कवर करना आवश्यक नहीं समझते हैं। उच्च न्यायालयों में राय की प्रधानता विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करने में भी है, और हम सही सोचते हैं।

निर्धारिती के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मेसर्स छत्तूराम होरिलराम लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बिहार और उड़ीसा () में इस न्यायालय का निर्णय एक अलग दृष्टिकोण का खुलासा करता है, और हमें बाद के गजेंद्रगडकर, जे. के दृष्टिकोण के बजाय इसका पालन करना चाहिए। हमें नहीं लगता कि पिछले उद्धृत मामले में भी मुद्दा वही था। वैक्टराम अय्यर, गजेंद्रगडकर और सरकार, जे.जे. की खंडपीठ के समक्ष इसी मामले पर भरोसा किया गया था और गजेंद्रगडकर, जे. ने इसे

अलग किया था। उन्होंने यही देखा:

"श्री शास्त्री ने धारा 34 के अपने निर्माण के समर्थन में मेसिरा में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। छत्तूराम होरिलराम लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बिहार और उड़ीसा ()। छत्तूराम के मामले में () एसोसेस आयकर का निर्धारण किया गया था जिसे अपील पर कम कर दिया गया था और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार

पर खारिज कर दिया गया था कि 1939 का भारतीय वित्त अधिनियम, छोटा नागपुर में मूल्यांकन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। एक संदर्भ पर निर्णय ट्रिब्यूनल को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। इसके बाद बिहार के राज्यपाल ने 1942 के बिहार विनियमन IV को प्रख्यापित किया और इस तरह छोटा नागपुर में 1939 के भारतीय वित्त अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया। 30 मार्च, 1939 से प्रभावी रूप से यह अध्यादेश लागू हुआ। गवर्नर- जनरल द्वारा सहमति दी गई। 8 फरवरी, 1944 को आयकर अधिकारी ने एक आदेश पारित किया जिसके अनुसरण में (1) (1953) एससी.आर. 19 के खिलाफ कार्यवाही की गई। धारा 34 के प्रावधानों के तहत निर्धारिती और उनके परिणामस्वरूप निर्धारिती का आयकर निर्धारण हुआ। इस न्यायालय में अपनी अपील में निर्धारिती द्वारा जो तर्क उठाया गया था वह यह था कि धारा 34 के तहत उसके खिलाफ जारी किया गया नोटिस अमान्य था। इस न्यायालय ने माना कि जिस आय, लाभ या लाभ टीएल का मूल्यांकन करने की मांग की गई थी, वह आयकर के लिए प्रभार्य था और यह धारा 34 के अर्थ के भीतर मूल्यांकन से बचने वाली प्रभार्य आय का मामला था और यह केवल आयकर के गैर-आकलन का मामला नहीं था। जहां तक फैसले का सवाल है, यह श्री शास्त्री द्वारा उठाए गए तर्क से पूरी तरह असंगत है। हालाँकि, वह जगन्नाथदास, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं, कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क कि मूल्यांकन से बचना गैर-मूल्यांकन सरलता के बराबर नहीं होना चाहिए, बिना बल के नहीं है और

वह बताते हैं अंतिम निर्णयों के समर्थन में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया कारण यह था कि यद्यपि पहले मूल्यांकन की कार्यवाही की गई थी, लेकिन आरोप- योग्यता के बावजूद मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों के कारण कुछ अन्य कमियों के कारण वे वैध मूल्यांकन में परिणाम देने में विफल रहे थे। कर के लिए आय. श्री शास्त्री का कहना है कि यह केवल उन मामलों में है जहां आय को 'आकलन प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य कमी के कारण मूल्यांकन से बचा हुआ दिखाया जा सकता है।' 34 का आह्वान किया जा सकता है. हमें नहीं लगता कि फैसले को निष्पक्ष रूप से पढ़ने से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. श्री शास्त्री द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे स्वाभाविक रूप से उन तथ्यों के संदर्भ में की गई हैं जिनसे न्यायालय निपट रहा था और उन्हें स्पष्ट रूप से उन तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यह सुझाव देना अनुचित होगा कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य एस के अनुप्रयोग को सीमित करना था। 34 केवल उन मामलों के लिए जहां आय मूल्यांकन अधिकारियों के कारण होने वाले कारणों के अलावा अन्य कारणों से मूल्यांकन से बच जाती है। वास्तव में जगन्नाथदास, जे. ने यह जोड़ने में सावधानी बरती है कि यह निर्धारित करना अनावश्यक है कि वास्तव में मूल्यांकन से बचना क्या है और यह कि उनके निर्णय को संकीर्ण आधार जिसका हमने अभी उल्लेख किया है, पर आधारित करना पर्याप्त होगा। हम संतुष्ट हैं कि इस निर्णय से अपीलकर्ता के मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी।"हमारे द्वारा दिए गए कारणों से, हमारी राय है कि कृषि आयकर अधिकारी अधिनियम की

धारा 26 के तहत आय की उस वस्तु का आकलन करने में सक्षम था जिस पर उसने पहले कर लगाना छोड़ दिया था, भले ही रिटर्न में उस आय को शामिल किया गया था और कृषि आयकर अधिकारी ने तब सोचा था कि यह छूट थी। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा दिया गया जवाब सही था.

यह हमें दूसरे प्रश्न पर लाता है। यह आय पट्टे पर दी गई संपत्तियों से प्राप्त हुई थी और यह कृषि आय थी। निर्धारिती का तर्क यह है कि टेकारी राज के हाथ में यह कृषि आय हो सकती है, लेकिन उनके हाथ में यह पूंजीगत प्राप्ति थी और लगभग रुपये का ऋण चुकाना था। रानी भुवनेश्वरी कुअर को 17,00,000 का भुगतान किया गया। हालाँकि, बिहार राज्य इस बात से इनकार करता है कि कोई ऋण या बंधक था। यह तर्क दिया गया है कि निर्धारिती को रुपये के किराए पर कई वर्षों तक कब्जे में रखा गया था। 1,000 प्रति वर्ष और भुगतान की गई राशि प्रीमियम थी न कि ऋण।

विचाराधीन दस्तावेज़ दो हैं. वे स्पष्ट रूप से रानी और निर्धारिती के बीच पट्टे के अनुबंध हैं। इन दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट है कि रुपये के भुगतान पर विचार किया जा रहा है। 17,16,000 रुपये की राशि में पट्टेदार को 28 वर्षों के लिए पट्टे की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया गया। ऐसी कोई स्पष्ट शर्त नहीं है जो ऋण की राशि को पुनर्भुगतान या भोग के आनंद के द्वारा वापस करने योग्य बनाती हो। इसमें कोई ब्याज तय नहीं है या मोचन का अधिकार नहीं दिया गया है। 28 वर्ष की अवधि के अंत

में कोई राशि बकाया रहने की स्थिति में किसी भी व्यक्तिगत दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। यह पता लगाने के लिए लागू होने वाले परीक्षण हैं कि क्या लेनदेन कार्पेशगी पट्टे में से एक था या बंधक के साथ पट्टे में से एक था। मुल्ला का संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, चौथा संस्करण, पृष्ठ 352 देखें।

निर्धारिती के विद्वान वकील ने अपने सावधानीपूर्वक तर्क में हमें दो दस्तावेजों से अवगत कराया और यह साबित करने का प्रयास किया कि देनदार और लेनदार का संबंध पार्टियों के बीच मौजूद था। उन्होंने हमें कॉलम संख्या 4 को रेफर किया, जो पट्टेदार को 12 प्रतिशत की कटौती करने का अधिकार देने वाले प्रावधान का प्रतीक है। पट्टादाता के लिए आरक्षित किराए के भुगतान के बाद वसूली और उससे जुड़े अन्य शुल्कों के व्यय के रूप में मुकर्ररदारों द्वारा देय सकल कुल राशि का और शेष को खुद के लिए उपयुक्त बनाना। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पट्टेदार को भुगतान प्रीमियम नहीं बल्कि ऋण था और इरादा यह था कि पट्टेदार पी या लेनदार को इस प्रकार चुकाया जाएगा। यह खंड अपने आप में विविध निर्माणों को स्वीकार कर सकता है, और संभवतः ऐसा एक निर्माण सुझाया गया हो सकता है, लेकिन वह बाकी उपकरण के संदर्भ में पढ़े गए खंड का सही अर्थ नहीं है। इस खंड की व्याख्या करने के लिए उपकरण को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और जब देखा जाता है, तो यह पाया जाता है कि यह संग्रह शुल्क के दायित्व से पट्टादाता को छूट प्रदान करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संग्रहण शुल्क पट्टेदार को डेबिट नहीं किया जाना था बल्कि पट्टेदार द्वारा वहन किया जाना था। जब तक इस तरह के प्रावधान को साधन में शामिल नहीं किया गया, यह कुछ विवाद का विषय हो सकता था कि इस व्यय के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

इसके बाद निर्धारिती के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान 31 जनवरी, 1936 के दस्तावेज़ के अंतिम खंड की ओर आकर्षित किया। हालाँकि, वह एक विशेष वाचा थी, और उसमें प्रावधान उन मामलों के संबंध में था जो दस्तावेज़ में शामिल नहीं थे।

इस पट्टे की संपत्ति, जो भूमि थी, से होने वाली आय "कृषि आय" की परिभाषा के अंतर्गत आएगी, इस पर हमारे सामने गंभीरता से विवाद नहीं हुआ था। निर्धारिती का मामला इस दावे पर टिका है कि यह एक धन- उधार लेनदेन था और रसीदें पूंजी रिटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि, तथापि, वेतन. पट्टेदार के लिए भुगतान प्रीमियम था न कि ऋण, इन पट्टेदारी संपत्तियों से आय, कृषि होने के कारण, अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य थी। हमारी राय है कि ऐसा ही था, और जब कृषि आयकर अधिकारी ने इसका आकलन कृषि आयकर के रूप में किया तो वह सही था। यह आय साहूकार की आय नहीं थी और यह प्राप्तकर्ता के चरित्र पर निर्भर नहीं करती थीका मुनाफ़ा स्पष्ट रूप से कृषि आय थी जो वास्तव में भूमि से प्राप्त होती थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न का उत्तर सही था। इसका परिणाम यह होता है कि अपील विफल हो जाती है, और

तदनुसार इसे लागत सहित खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संयोगिता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।